

यूपी को वर्ष 2000-17 की तुलना में 2019-23 में चार गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 'यूपी: भारत में वदेशी निवेश के लिये एक उभरता हुआ गंतव्य' सम्मेलन का उद्घाटन किया।

मुख्य बटु:

- सम्मेलन के दौरान सीएम ने बताया कविरूष 2000-2017 की तुलना में वर्ष 2019-23 में यूपी को चार गुना ज़्यादा [परतयकष वदेशी नविश \(FDI\)](#) मलिा ।
 - आधकिारकि बयान के मुताबकि, राज्य सरकार प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के लयि नरिधारति लकष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी ।
 - पछिले 6-7 वर्षों में राज्य की छवबिदली है । सात वर्ष पहले यूपी देश का बीमारू (BIMARU) राज्य हुआ करता था ।
- सीएम के मुताबकि बढा हुआ नविश बेहतर कानून व्यवस्था का नतीजा है ।

बीमारू (BIMARU)

- यह बहिर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संकषपित रूप है, जो उन राज्यों का समूह है जो ऐतहिसकि रूप से आर्थकि तथा सामाजकि संकेतकों में पछिडे हुए हैं ।
- इन राज्यों की वशिषता उच्च स्तर की गरीबी, कम साकषरता दर और खराब बुनयिादी ढाँचा है ।
- ऐसे कई कारक हैं जनिहोंने इसमें योगदान दिया है, जनिमें शामिल हैं:
 - **नविश की कमी:** इन राज्यों को ऐतहिसकि रूप से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार से कम नविश प्राप्त हुआ है । इससे बुनयिादी ढाँचे के वकिास में कमी आई है, जसिसे इन राज्यों में व्यवसायों का संचालन करना मुश्कलि हो गया है ।
 - **खराब शासन:** बीमारू राज्य भी खराब शासन से त्रस्त हैं । इसके परणामस्वरूप भ्रषटाचार, भाई-भतीजावाद और पारदर्शतिा की कमी हुई है । इससे इन राज्यों में व्यवसायों के लयि कार्य करना मुश्कलि हो गया है तथा नविश भी हतोत्साहति हुआ है ।
 - **उच्च जनसंख्या वृद्धि:** बीमारू राज्यों ने भी उच्च जनसंख्या वृद्धिदर का अनुभव कयिा है । इससे संसाधनों पर दबाव पड़ा है और इन राज्यों की सरकारों के लयि अपने नागरिकों को बुनयिादी सेवाएँ प्रदान करना मुश्कलि हो गया है ।

FDI and FPI



Foreign Direct Investment (FDI)

About:

- Investment made by foreign entities/individuals in **businesses and assets** located in a different country

FDI Routes:

Automatic Route:

- No prior government approval required
- Up to 100% allowed in non-critical sectors

Government Approval:

- Necessary in certain sectors or for investments above specific thresholds
- Administered by **Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)** and RBI

Examples of Approval via Auto and Govt Route:

- Banking (Private sector): up to 49% (auto) + above 49% and up to 74% (Govt)
- Defence: up to 74% (auto) + above 74% (Govt)
- Healthcare (Brownfield): up to 74% (auto) + above 74% (Govt)
- Telecom Services: up to 49% (auto) + above 49% (Govt)

Foreign Investment Promotion Board (FIPB):

- Comes under Ministry of Finance
- Responsible for processing FDI proposals - facilitated by **Foreign Investment Facilitation Portal (FIFP)**
- Making recommendations for Government approval

Govt's prior approval is mandatory for FDI from countries sharing land border with India (China, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Myanmar and Afghanistan)

India's Top 5 FDI Sources (FY 2022-23):

- Mauritius
- Singapore
- USA
- Netherlands
- Japan

India's Top Sectors Attracting FDI (FY 2022-23):

- Services Sector
- Computer Software & Hardware
- Trading
- Telecommunications
- Automobile Industry



Foreign Portfolio Investment (FPI)

About:

- Investments made by foreign individuals, institutions, or funds in financial assets
- Known as Fly by Night or Hot Money

Imp Features:

- Purchase of financial assets** occur without gaining ownership
- Passive investment approach
- Investors earn returns through **dividends, interest, and capital appreciation**

Example:

- Stocks, Bonds etc.

Regulatory Body:

- Securities and Exchange Board of India (SEBI)

Difference between FDI and FPI

Features	FDI	FPI
Nature of Investment	Long-term	Short-term
Objective	Long-term presence in a foreign country	Earning quick returns on investments
Control	Significant (over the invested entity)	No or limited control
Investments in	Tangible assets (e.g., factories, buildings)	Financial assets (e.g., stocks, bonds)
Returns	Profits, Dividends, and Capital appreciation	Dividends, Interest, and Capital appreciation
Policy Regulations	Govt policies and sector-specific regulations	Flexible regulations and easier entry/exit
Impact on Economy	Job creation, technology transfer, and economic growth	Short-term liquidity and impact on stock market performance

